Demand of enhanced royalty for crude oil by Gujarat

*417. SHRI A. N. MULLA :

SHRI UMASHANKAR JOSHI :t

SHRI YOGENDRA SHARMA :

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI:

SHRIMATI SUMITRA G. KULKARNI:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the answer to Starred Question 707 J given in the Rajya Sabha on the 26th August, 1974 and state what is the present stage of negotiations with the Gujarat Government in regard to enhancement of rate of royalty on crude oil and when a final decision is likely to be taken ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI K. D. MALAVIYA) : The matter is under examination.

श्री योगेन्द्र शर्मा : अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह सवाल अभी विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कब से विचाराधीन है और कब तक विचाराधीन रहेगा ? श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ भी खींचना चाहूंगा कि रायलटी का सवाल अभी गुजरात के साथ भी चल रहा है और इसी तरह की बातचीत आसाम के साथ भी उठी है। क्योंकि वहां भी क्रूड आयल और उसकी रायलटी का सवाल है। तो वहां पर क्या तय किया गया है? रायलटी की क्या दर असम में रखी गई है और क्या इसकी दर गुजरात में है और गुजरात ने क्या मांग की है? रायलटी को तय करने में किन-किन बातों को कंसिडरेशन में लिया जाता है, क्योंकि अभी तो क्रूड का ही सवाल है; मेरा ख्याल है कि एनर्जी का दूसरा सोर्स कोयला है और वहां भी सवाल उठा है कि रायलटी जब हम तय करते हैं तो एड हाक बेसिस पर तय करते हैं या किसी प्रिंसिपल की बेसिस पर तय करते हैं। मेरा ख्याल है कि समय आ गया है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और रायलटी तय करने का कुछ प्रिंसिपल इवाल्व करना चाहिए नहीं तो फिर एड हाक बेसिस पर यह फिर झगड़ा होता रहेगा। तो मैं अपना सवाल फिर दुहरा दूं कि कब से कंसिडरेशन स्टेज में है, कब तक कंसिडरेशन में रहेगा और रायलटी तय करने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए हैं, और असम में भी क्या यही सवाल उठा हुआ है, असम में जो रायलटी की दर है वह क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : रायलटी का सवाल समय-समय पर तय होता जाता है। एक समय साढ़े 7 रु० टन था, उसके बाद 10 रु० टन हो गया, उसके बाद 15 रु० हो गया। जब कभी असम और गुजरात से यह सुझाव आता है कि रायलटी में वृद्धि की जाए तो सरकार ने एक तरीका बना लिया है, उस तरीके के मुताबिक उस पर विचार किया जाता है। जिस बुनियाद के ऊपर रायलटी की वृद्धि की मांग की जाती वह यह है कि चीजें महंगी होती जाती है, प्रदेश की सरकारों की मांग बढ़ती जाती है। वह चाहते हैं उनकी आमदनी बढ़े, इसके लिए रायलटी में वृद्धि हो। एक सीमित रूप में रायलटी वृद्धि होना संभव नहीं है। वह हमी को देना चाहिए, चाहे इस हाथ से दें चाहे उस हाथ दें। रायलटी की वृद्धि मुनासिब मांग है और वह इस समय विचाराधीन है। मौजूदा समय तेल की महंगाई और सब चीजों की महंगाई बढ़ती गई है और इन सब बातों पर विचार कर रायलटी में किस अनुपात में वृद्धि की जाए तय किया जाएगा। गुजरात और असम, दोनों जगहों से रायलटी की वृद्धि की मांग आई और मुझे आशा है कुछ ही हफ्तों के अन्दर इस पर सरकार का निश्चय हो जाएगा।

t The question was actually asked on the floor of the House by Shri Umashankar Joshi.

96 RSS/74—2.

SHRIMATI SUMITRA G. KULKARNI: Sir, some time back, Dr. V. K. R. V. Rao Commission gave an award. It has fixed some principles and on the basis of those principles, Rs. 15 per ton of crude was the royalty given to Gujarat. Since the price of crude has gone up so many times since 1973, keeping in view the principles that Dr. V. K. R. V. Rao Commission has laid down, would the hon. Minister tell me how much would the royalty be on the present value of crude? What is the arithmatic of it? How much will it be on the basis of the award that was given by Dr. V. K. R. V. Rao ? This is *my* first point.

SHRI K. D. MALAVIYA: First of all, the impression that the international price of crude oil is also the price that the Government pays to the Oil and Natural Gas Commission should be removed. The Oil and Natural Gas Commission gets much less price than what the international price is. They get about $3.50 as against the international price of 10 or 11 dollars. Therefore, it will not be fair to link the royalty rate with the international price. The Prime Minister gave an award on the basis of the report that was given by Dr. V. K. R. V. Rao and Rs. 15 were fixed on that basis. We are again reviewing, and 12 NoWf the situation underlying those principles has now changed. The demands from the Assam Government and the Gujarat Government are different and they are on different basis. And those differences in basis are now being considered. As the Government are very sympathetically considering this question, I would suggest to the tion. Member not to press much about this so that we may be able to expedite ihe decision and try to satisfy the State jovernments.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is >ver.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हाजीपुर, लाल गंज और वैशाली होकर सगौली तक रेल लाइन का निर्माण

*418. श्री सीताराम सिंह :

श्री राजनारायण :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाजीपुर, लाल गंज और वैशाली होते हुए सगौली तक रेल लाइन का निर्माण करने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त रेल लाइन का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

Rail link upto Sagauli via Hajipur, Lalgaoj

*418. SHRI SITARAM SINGH : SHRI RAJNARAIN:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum for providing rail link upto Sagauli via Hajipur, Lalganj and Vaishali;

(b) if so, the reaction of Government in this regard; and

(c) by when the said rail link will be pro vided?]

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस रेल सम्पर्क के लिए अभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । औद्योगिक अथवा अन्य किसी प्रकार के विकास का कोई ज्ञात कार्यक्रम न होने के कारण और धन की कमी के कारण भी, हो सकता है कि निकट भविष्य में प्रस्तावित रेल सम्पर्क को हाथ में लेना संभव न हो पाये ।

t[ ] English translation